



सत्यमेव जयते

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955  
(Hindu Marriage Act, 1955)

# हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

## ( 1955 का अधिनियम संख्या 25 )

[ 18 मई 1955 ]

### प्रारम्भिक

#### 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार –

- (1) यह अधिनियम [हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955](#) कहलाया जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जिन राज्य-क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य-क्षेत्रों में अधिवासी उन हिन्दुओं को भी यह लागू है जो उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं।

### PRELIMINARY

**1. Short title and extent —** (1) This Act may be called the [Hindu Marriage Act, 1955](#).

(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by [Act 34 of 2019](#), s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this Act extends, who are outside the said territories.

#### 2. अधिनियम का लागू होना-

(1) यह अधिनियम -

(क) वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्म, प्रार्थना या आर्य-समाज के अनुयायियों के सहित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि हिन्दू धर्म के रूपों के विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिन्दू हैं;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिक्ख हैं; और

(ग) जब तक कि उन राज्य-क्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी किसी बात के बारे में, जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, हिन्दू विधि द्वारा या उस विधि की भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी लागू है।

**स्पष्टीकरण** – निम्न व्यक्ति अर्थात् :-

(क) ऐसा कोई बालक चाहे वह औरस हो या जारज जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हों;

(ख) ऐसा बालक चाहे वह औरस हो या जारज जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख है और जिसका कि लालन-पालन उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है जिसका कि ऐसा जनक है या था; और

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म ग्रहण किया है, पुनर्ग्रहण किया है; यथास्थिति धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थों के अन्दर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को तब तक लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे।

(3) इस अधिनियम के किसी प्रभाव से हिन्दू पद का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो कि इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिन्दू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के बल से लागू होता है।

## 2. Application of Act -

(1) This Act applies :

(a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;

(b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion; and

(c) to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

**Explanation -** The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be :

(a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion;

(b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged; and

(c) any person who is a convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.

(3) The expression "Hindu" in any portion of this Act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.

**3. परिभाषाएँ -** इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "रुढ़ि" और "प्रथा" पदों से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे कि लम्बे समय के लिए लगातार और एकरूपता से अनुपालित किये जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है : परन्तु यह तब जब कि यह नियम निश्चित हो, और अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो और, परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की अवस्था में जो कि एक ही परिवार को लागू है, परिवार द्वारा उनका अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया हो।

(ख) "जिला न्यायालय" से ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके लिए नगर व्यवहार न्यायालय है, वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्राधिकार वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य व्यवहार न्यायालय है जिसे कि इस अधिनियम में जिन बातों के लिए व्यवस्था की गई है उनके बारे में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित किया जाये।

(ग) "सगा" और 'सौतेला' - कोई दो व्यक्ति एक-दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक पत्नी से जन्में हों, और सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किन्तु उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हों।

(घ) "सहोदर" दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किन्तु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हों।

स्पष्टीकरण - खण्ड (ग) और (घ) में 'पूर्वज' पद के अन्तर्गत पिता है और 'पूर्वजा' के अन्तर्गत माता है।

(ड.) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(च) (i) किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक (जिसके अन्तर्गत तीसरी पीढ़ी भी है) और पिता के ऊपर वाली परम्परा में पाँचवीं पीढ़ी तक (जिनके अन्तर्गत पाँचवीं पीढ़ी भी है), प्रत्येक अवस्था में परम्परा सम्पृक्त व्यक्ति से ऊपर गिनी जायेगी जिसे कि पहली पीढ़ी का गिना जाता है;

(ii) यदि दो व्यक्तियों में से एक सपिंड की नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परम्परागत अग्रपुरुष है, या यदि उसका ऐसा एक ही परम्परागत अग्रपुरुष है, जो कि एक-दूसरे के प्रति सपिंड नातेदार की सीमाओं के भीतर है; तो ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि वे एक-दूसरे के सपिंड हैं।

(छ) “प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ” - यदि दो व्यक्तियों में से सान्निध्य:-

(i) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपुरुष है, या

(ii) एक-दूसरे का परम्परागत अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी या पति है; या

(iii) एक-दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, या पितामह या मातामह या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है; या

(iv) भाई और बहिन, चाचा और भतीजी, चाची या भतीजा या भाई और बहिन की या दो भाइयों या दो बहिनों की सन्तति हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे 'प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों' के अन्दर हैं।

स्पष्टीकरण - खण्ड (च) और (छ) के प्रयोजनों के लिये 'नातेदार' के अन्तर्गत -

(i) सभी नातेदारी के समान ही सौतेली या सहोदर नातेदारी भी है;

(ii) औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है;

(iii) रक्तजन्य नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है;

और उन खण्डों में नातेदारी सम्बन्धी पदों का अर्थ तदनुकूल लगाया जायेगा।

**3. Definitions —** In this Act, unless the context otherwise requires :

(a) the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family :

Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and

Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family;

(b) "district Court" means, in any area for which there is a City Civil Court, that Court, and in any other area the principal Civil Court of original jurisdiction, and includes any other Civil Court which may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act;

(c) "full-blood" and "half-blood" - two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives;

(d) "Uterine blood" - two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands;

**Explanation -** In clauses (c) and (d), "ancestor" includes the father and "ancestress" the mother;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) (i) "sapinda relationship" with reference to any person extends as far as the third generation (inclusive) in the line of ascent through the mother, and the fifth (inclusive) in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned, who is to be counted as the first generation;

(ii) two persons are said to be "sapindas" of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of sapinda relationship, or if they have a common lineal ascendant who is within the limits of sapinda relationship with reference to each of them;

(g) "degrees of prohibited relationship" - two persons are said to be within the "degrees of prohibited relationship" -

(i) if one is a lineal ascendant of the other; or

(ii) if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other; or

(iii) if one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother or of the grandfather's or grandmother's brother of the other; or

(iv) if the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister or of two brothers or of two sisters;

**Explanation —** For the purposes of clauses (f) and (g), relationship includes

(i) relationship by half or uterine blood as well as by full blood;

(ii) illegitimate blood relationship as well as legitimate;

(iii) relationship by adoption as well as by blood; and all. Terms of relationship in those clauses shall be construed accordingly.

**4. अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव-** इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्तरूपेण उपबन्धित को छोड़कर:-

(क) हिन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूपी रूढ़ि या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से अव्यवहितपूर्व प्रवृत्त थी, ऐसी किसी बात के बारे में प्रभावशून्य हो जायेगी जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है।

(ख) कोई अन्य विधि जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहितपूर्व प्रवृत्त थी, वहाँ तक प्रभावशून्य हो जायेगी जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी से असंगत है।

#### **4. Overriding effect of Act —** Save as otherwise expressly provided in this Act

(a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;

(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act.

### **हिन्दू विवाह**

**5. हिन्दू विवाह के लिए शर्तें-** दो हिन्दुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्न शर्तें पूरी की जाती हों, अर्थात् –

(i) दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है।

(ii) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार –

(क) चित्त विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो; या

(ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह और सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हो; या

(ग) उसे उन्मत्तता का दौरा बार-बार पड़ता हो।

(iii) वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली है;

(iv) जब कि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, तब पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हैं;

(v) जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो तब पक्षकार एक-दूसरे के सपिण्ड नहीं हैं।

## **CHAPTER II :**

### **HINDU MARRIAGES**

**5. Conditions for a Hindu marriage –** A marriage may be solemnized between any two Hindus, if the following conditions are fulfilled, namely –

- (i) neither party has a spouse living at the time of the marriage;
- (ii) at the time of the marriage, neither party
- (a) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind;  
or
- (b) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or
- (c) has been subject to recurrent attacks of insanity
- (iii) the bridegroom has completed the age of twenty-one years and the bride, the age of eighteen years at the time of the marriage;
- (iv) the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two;
- (v) the parties are not sapindas of each other, unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two;

### Commentary and Case Laws

1. **सेक्शन 5 के अंतर्गत दो सपिन्दा अथवा प्रतिसिद्ध नातेदारी के बीच विवाह, उन प्रकरणों को छोड़कर जिसमें ऐसा किया जाना दोनों पक्षों के कस्टम अथवा रूढ़ियों प्रचलित में है , किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर शून्य होगा (Under Section 5, the marriage between the Sapindas or within prohibited degree, unless the custom and usage of each of the party permits such a marriage, shall be void on a petition preferred by either party thereto) .[\[RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated 15.11.2019\]](#) – The Supreme Court has held that –**
  - In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same caste and with the permission and consent of both of their fathers, they have entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.
  - The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of



customary rites and ceremonies. The burden to prove marriage was on the Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. Such marriage is a void marriage but, on a petition, preferred by either party thereto.

- Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites, therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged registration of an agreement of marriage.
- In the present case, the plaintiff has not proved custom of marriage to her mother's brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence of such custom.
- The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.

**6. विवाहार्थ संरक्षकता --** बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2), धारा 6 और अनुसूची द्वारा (1-10-1978 से) विलोपित।

**6. Guardianship in marriage -** [Omitted by the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978 (2 of 1978), section 6 and Schedule (w.e.f. 1-10-1978).]

**7. हिन्दू विवाह के लिए संस्कार-**

(1) हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रुढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा।

(2) जहाँ कि ऐसे आचार और संस्कारों के अन्तर्गत सप्तपदी है (अर्थात् अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्त सात पद लेना है) वह विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबकि सातवाँ पद पूरा किया जाता है।

## 7. Ceremonies for a Hindu marriage -

(1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto.

(2) Where such rites and ceremonies include the saptpadi (that is, the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.

### Commentary and Case Laws

1. विवाह का एग्रीमेंट कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाने मात्र से सेक्शन 7 के तहत विवाह होना प्रमाणित नहीं होता जब तक कि यह न बताया जाये कि यह विवाह किस कस्टम से किया गया था एवं यदि कस्टम में सप्तपदी सम्मिलित हो तब ऐसी दशा में क्या सातवाँ पद पूरा किया गया ( Mere production of agreement of marriage before the court does not prove the marriage unless it is disclosed by which custom the marriage was solemnised and if the custom included Sapdpadi, whether the seventh step was completed) - [\[RATHNAMMA & ORS. VERSUS SUJATHAMMA & ORS.:SC dated 15.11.2019\]](#)  
-The Supreme Court has held that -
  - In the agreement of marriage (Ex.P/1), it is only stated that both parties are of same caste and with the permission and consent of both of their fathers, they have entered into this agreement of marriage. This type of marriage is not recognized in law as Section 7 of the Act contemplates that the marriage can be solemnized in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto and where such rites and ceremonies include the Saptpadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.
  - The plaintiff has not led any evidence of solemnization of marriage as provided under sub-clause (2) of Section 7 of the Act or by leading any evidence of customary rites and ceremonies. The burden to prove marriage was on the Plaintiff alone. The defendants have denied marriage of the Plaintiff, therefore, the burden to prove marriage was on the plaintiff alone. Apart from such fact, the marriage cannot be said to be taken place in terms of Section 5(v) of the Act which is to the effect that the parties are not sapindas to each other, unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two.

Such marriage is a void marriage but, on a petition, preferred by either party thereto.

- Therefore, the question required to be examined is whether the alleged marriage which is between the persons of less than 21 years and 18 years and between the Prohibited degree is a valid marriage. The plaintiff will be entitled to the estate of Hanumanthappa only if she proves her valid marriage. The plaintiff has not pleaded any custom permitting marriage within the prohibited degree nor there is any proof of solemnization of any marriage by customary ceremonies and rites, therefore, the plaintiff will not be entitled to succeed only on the basis of alleged registration of an agreement of marriage.
- In the present case, the plaintiff has not proved custom of marriage to her mother's brother and/or judicial precedent recognizing such marriage. In the absence of any precedent or custom of such marriage, no judicial notice can be taken of a custom as argued by the learned counsel for the plaintiff. In the absence of any pleading or proof of custom, the argument that in Vokkaliga community, such marriage can be performed cannot be accepted as no judicial precedent was brought to the notice of the Court that such a custom exists in the Vokkaliga community nor there is any instance quoted in evidence of existence of such custom.
- The entire case is based upon an agreement of marriage in which there is no assertion regarding solemnization of the customary ceremonies or the rites or that the parties had performed saptpadi in the manner contemplated under Section 7 of the Act, therefore, the plaintiff cannot succeed the estate of Hanumanthappa on the basis of a marriage which she has failed to prove.

## 8. हिन्दू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण -

(1) राज्य सरकार हिन्दू-विवाहों की सिद्धि को सुकर करने के प्रयोजन के लिए यह उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से सम्बद्ध विशिष्टयाँ इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले हिन्दू-विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहकर जैसी कि विहित की जायें, प्रविष्ट कर सकेंगे।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो यह उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह उपबन्ध कर सकेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को प्रविष्ट करना उस राज्य में या उसके किसी भाग में या तो सब अवस्थाओं में या ऐसी अवस्थाओं में जैसी कि उल्लिखित की जायें, अनिवार्य होगा और जहाँ कि ऐसा कोई निर्देश निकाला गया है, वहाँ इस निमित्त बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति जुमनि से जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सब नियम अपने बनाये जाने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

(4) हिन्दू-विवाह रजिस्टर सब युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उसमें अन्तर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे और रजिस्ट्रार आवेदन किये जाने पर और अपने की विहित फीस की देनगियाँ किये जाने पर उसमें से प्रमाणित उद्धरण देगा।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी हिन्दू-विवाह की मान्यता ऐसी प्रविष्टि करने में कार्यलोप के कारण किसी अनुरीति में प्रभावित न होगी।

## **8. Registration of Hindu marriages -**

(1) For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the State Government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu Marriage Register kept for the purpose.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in sub-section (1) shall be compulsory in the State or in any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, and where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees.

(3) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature, as soon as may be, after they are made.

(4) The Hindu Marriage Register shall at all reasonable times be open for inspection, and shall be admissible as evidence of the statements therein contained and certified extracts there from shall, on application, be given by the Registrar on payment to him of the prescribed fee.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry.

## **दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण**

### **9. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन -**

जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिये याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किये गये कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है; अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आज्ञा देगा।

**स्पष्टीकरण -** जहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है।

## CHAPTER III

### RESTITUTION OF CONJUGAL RIGHTS AND JUDICIAL SEPARATION

**9. Restitution of conjugal rights -** When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district Court, for restitution of conjugal rights and the Court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly.

**Explanation -** Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.

#### 10. न्यायिक पृथक्करण -

(1) विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात् जिला न्यायालय की धारा 13 की उपधारा (1) में और पत्नी की दशा में उसी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी ऐसे आधार पर, जिस पर विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थापित की जा सकती थी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी उपस्थापित कर सकेगा।

(2) जहाँ कि न्यायिक पृथक्करण के लिये आज्ञप्ति दे दी गई है, वहाँ याचिकादाता आगे के लिये इस आभार के अधीन होगा कि प्रत्युत्तरदाता के साथ सहवास करे, किन्तु यदि न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा याचिका द्वारा आवेदन पर ऐसी याचिका में किये गये कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर वैसा करना न्याय संगत और युक्तियुक्त समझे तो वह आज्ञप्ति का विखंडन कर सकेगा।

#### 10. Judicial separation -

(1) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection (1) of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds specified in sub-section (2) thereof, as grounds on which a petition for divorce might have been presented.

(2) Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the Court may, on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the

statements made in such petition, rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so.

## विवाह की अकृतता और तलाक

**11. शून्य विवाह -** इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठित किया गया यदि कोई विवाह धारा 5 के खण्ड (1), (4) और (5) में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है, तो वह अकृत और शून्य होगा और उसमें के किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृतता की आज्ञा दी जा सकेगी।

## CHAPTER IV

### NULLITY OF MARRIAGE AND DIVORCE

**11. Void marriages -** Any marriage solemnized after the commencement of this Act shall be null and void and may, on a petition presented by either party thereto (against the other party), be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses (i), (iv) and (v) of section 5.

## 12. शून्यकरणीय विवाह -

(1) कोई विवाह भले ही वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठित किया गया है; निम्न आधारों में से किसी पर अर्थात्:

(क) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है; या

(ख) इस आधार पर कि विवाह धारा 5 के खण्ड (2) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में है; या

(ग) इस आधार पर कि याचिकादाता की सम्मति या जहाँ कि याचिकादाता के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति, धारा 5 के अनुसार बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के लागू होने के पूर्व थी वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बल या कर्म-काण्ड की प्रकृति या प्रत्यर्थी से सम्बन्धित किसी तात्त्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी, या

(घ) इस आधार पर कि प्रत्युत्तरदात्री विवाह के समय याचिकादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी; शून्यकरणीय होगा और अकृतता की आज्ञा दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विवाह को अकृत करने के लिए कोई याचिका:

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित आधार पर उस सूरत में ग्रहण न की जायेगी जिसमें कि -

(i) अर्जी, यथास्थिति, बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष पश्चात् दी जाए; या

(ii) अजींदार, यथास्थिति, बल प्रयोग के प्रवर्तन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात् विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सहमति से पति या पत्नी के रूप में रहा या रही है;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित आधार पर तब तक ग्रहण न की जायेगी जब तक कि न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है -

(i) कि याचिकादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ था;

(ii) कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित विवाहों की अवस्था में कार्यवाहियाँ ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठित विवाहों की अवस्था में विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित कर दी गई हैं; और

(iii) कि याचिकादाता की सम्मति से वैवाहिक सम्मोग उक्त आधार के अस्तित्व का पता याचिकादाता को चल जाने के दिन से नहीं हुआ है।

## **12. Voidable marriages –**

(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely -

(a) that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent; or

(b) that the marriage is in contravention of the condition specified in clause (ii) of section 5; or

(c) that the consent of the petitioner, or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner [was required under section 5, as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978 (2 of 1978)], the consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstance concerning the respondent]; or

(d) that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no petition for annulling a marriage :

(a) on the ground specified in clause (c) of sub-section (1), shall be entertained if :

(i) the petition is presented more than one year after the force had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered; or



(ii) the petitioner has, with his or her full consent, lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered;

(b) on the ground specified in clause (d) of sub-section (1) shall be entertained unless the Court is satisfied

(i) that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;

(ii) that proceedings have been instituted in the case of a marriage solemnized before the commencement of this Act within one year of such commencement and in the case of marriages solemnized after such commencement within one year from the date of the marriage; and

(iii) that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground.

### 13. तलाक-

(1) कोई विवाह, भले वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गयी याचिका पर तलाक की आज्ञा द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है कि -

(i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति, के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है; या

(i-क) विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है; या

(i-ख) अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है; या

(ii) दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिन्दू होने से परिवर्तित हो गया है, या

(iii) दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत-चित रहा है लगातार या आन्तरायिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्ति-युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे।

### स्पष्टीकरण -

(क) इस खण्ड में 'मानसिक विकार' अभिव्यक्ति से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता अभिप्रेत है और इनके अन्तर्गत विखंडित मनस्कता भी है;

(ख) 'मनोविक्षेप विषयक विकार' अभिव्यक्ति से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या अशक्तता (चाहे इसमें वृद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं) अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य



रूप से आक्रामक या गम्भीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और उसके लिये चिकित्सा उपचार अपेक्षित हो या नहीं, या किया जा सकता हो या नहीं, या

(iv) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है; या

(v) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित यौन-रोग से पीड़ित रहा है; या

(vi) दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है; या

(vii) दूसरे पक्षकार के बारे में सात वर्ष या अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में, यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है।

## स्पष्टीकरण -

इस उपधारा में 'अभित्यजन' पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अभित्यजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है और इस पद के व्याकरणिक रूपभेद तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार किये जायेंगे।

(1-क) विवाह में का कोई भी पक्षकार चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले अथवा पश्चात् अनुष्ठित हुआ हो, तलाक की आज्ञा द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए इस आधार पर कि

(i) विवाह के पक्षकारों के बीच में, इस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा के पारित होने के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है; अथवा

(ii) विवाह के पक्षकारों के बीच में, उस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञा के पारित होने के एक वर्ष पश्चात् एक या उससे अधिक की कालावधि तक, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है;

याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

(2) पत्नी तलाक की आज्ञा द्वारा अपने विवाह-भंग के लिए याचिका :-

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारम्भ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है या पति की ऐसे प्रारम्भ से पूर्व विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिकादात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी;

परन्तु यह तब जब कि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किये जाने के समय जीवित हो; या

(ii) इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है; या

(iii) कि हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन (या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की तत्स्थानी धारा 488 के अधीन) कार्यवाही में यथास्थिति, डिक्री या आदेश, पति के विरुद्ध पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किये जाने के समय से पक्षकारों में एक वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है; या

(iv) किसी स्त्री ने जिसका विवाह (चाहे विवाहोत्तर सम्भोग हुआ हो या नहीं) उस स्त्री के पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् किन्तु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है।

**स्पष्टीकरण** – यह खण्ड लागू होगा चाहे विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68) के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो या उसके पश्चात्।

### 13. Divorce -

(1) Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party -

(i) has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse; or

(ia) has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty; or

(ib) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition; or

(ii) has ceased to be a Hindu by conversion to another religion; or

(iii) has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent.

**Explanation** - In this clause : (a) the expression "mental disorder" means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia; the expression "psychopathic disorder" means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including sub-normality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment; or

(iv) has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy; or

(v) has been suffering from venereal disease in a communicable form; or

(vi) has renounced the world by entering any religious order; or

(vii) has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those persons who would naturally have heard of it, had that party been alive;

**Explanation —** In this sub-section, the expression “desertion” means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of such party, and includes the wilful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly.

(1A) Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground –

(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties; or

(ii) that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties.

(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground

(i) in the case of any marriage solemnized before the commencement of this Act, that the husband had married again before such commencement or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner:

Provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition; or

(ii) that the husband has, since the solemnization of the marriage, been guilty of rape, sodomy or bestiality; or

(iii) that in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), or in a proceeding under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) (or under the corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898)], a decree or order, as the case may be, has been passed against the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart

and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for one year or upwards;

(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized before she attained the age of fifteen years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of eighteen years.

**Explanation –** This clause applies whether the marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976).]

### Commentary and Case Laws

1. A. लंबे समय तक अलग रहना मात्र, तलाक का आधार नहीं हो सकता. अन्य तथ्यों को भी देखना आवश्यक (Mere long separation cannot be only ground for divorce, other facts are also to be seen)

B. किसी भी पक्ष द्वारा दहेज सम्बन्धी क्रिमिनल मुकदमा जीतने का तथ्य ऊपरी न्यायालय में स्वमेव तलाक का आधार नहीं हो सकता जबकि यह आधार निचली अदालत में तलाक के केस में न रहा हो ( Mere acquittal in criminal case relating to dowry cannot be the ground automatically for divorce petition in the Higher Court unless it was the ground in divorce case in Lower Court) [[Mangayakarasi Versus M. Yuvaraj-SC dated 03.03.2020](#)]- Supreme Court held that-

1. The position of law is well settled that neither the High Court in the limited scope available to it in a Second Appeal under Section 100 of the Civil Procedure Code is entitled to reappraise the evidence nor this Court.
2. Questions raised does not qualify as substantial questions of law when the manner in which the parties had proceeded before the Trial Court is noticed. The questions framed in fact provides scope for reappraisal of the evidence and not as substantial questions of law. If that be the position, a situation which was not the basis for initiating the petition for dissolution of marriage and when that was also not an issue before the Trial Court so as to tender evidence and a decision be taken, the High Court was not justified in raising the same as a substantial question of law and arriving at its conclusion in that regard. A perusal of the judgment of the High Court indicates that there is no reference whatsoever with regard to the evidence-based on which the dissolution of marriage had been sought, which had been declined by the Trial Court and the First Appellate Court and whether such consideration had raised any substantial question of law.
3. The tenor of the substantial questions of law as framed in the instant case and decision taken on that basis if approved, it would lead to a situation that in every case if a criminal case is filed by one of the parties to the

marriage and the acquittal therein would have to be automatically treated as a ground for granting divorce which will be against the statutory provision.

4. In cases where there has been a long period of continuous separation and the marriage becomes a fiction it would be appropriate to dissolve such marriage. On the position of law enunciated it would not be necessary to advert in detail inasmuch as the decision to dissolve the marriage apart from the grounds available, will have to be taken on case to case basis and there cannot be a strait jacket formula. This Court can in any event exercise the power under Article 142 of the Constitution of India in appropriate cases. However, in the instant facts, having given our thoughtful consideration to that aspect we notice that the parties hail from a conservative background where divorce is considered a taboo and further they have a female child born on 03.01.2007 who is presently aged about 13 years.
5. In a matter where the differences between the parties are not of such magnitude and is in the nature of the usual wear and tear of marital life, the future of the child and her marital prospects are also to be kept in view, and in such circumstance the dissolution of marriage merely because they have been litigating and they have been residing separately for quite some time would not be justified in the present facts, more particularly when the restitution of conjugal rights was also considered simultaneously.
6. In that view, having arrived at the conclusion that the very nature of the substantial questions of law framed by the High Court is not justified and the conclusion reached is also not sustainable, the judgment of the High Court is liable to be set aside.

2. A. पत्नी द्वारा साथ रहने की मात्र औपचारिक सहमति दिया जाना, जबकि वह वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठाने एवं सही में साथ रहने हेतु तैयार नहीं, पति द्वारा डिक्ली प्राप्त करने के प्रयास को निरर्थक करना ही कहा जा सकता है. ऐसी सहमति डिक्ली न दिए हेतु पर्याप्त कारण नहीं है ( Mere giving formal willingness by the wife to live together, whereas she is not ready to make adjustment in married life and really not willing to live together, this is only to frustrate the endeavour of the husband to get a decree of divorce. Such willingness is not sufficient for not giving the decree.)

B. यद्यपि तलाक के कानून में तलाक के आधार में असुधारयोग्य विवाह का विघटन का आधार सम्मिलित नहीं है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय किये जाने के प्रयोजन से यह अधिकार प्राप्त है, अतः इस आधार पर तलाक की डिक्ली जारी की गई. ( Although the ground of irretrievable of marriage is not inserted in the law of divorce, yet the Supreme Court has unique power to grant decree of divorce for doing complete

justice under Article 142 of the Constitution and decree was divorce was granted.)  
[\[MUNISH KAKKAR VERSUS NIDHI KAKKAR: SC dated 17.12.2019\]](#)– Hon. Supreme Court held that–

1. The fact, however, remains that the relationship appears to have deteriorated to such an extent that both parties see little good in each other, an aspect supported by the counselor's report; though the respondent insists that she wants to stay with the appellant. In our view, this insistence is only to somehow not let a decree of divorce be passed against the respondent. This is only to frustrate the endeavour of the appellant to get a decree of divorce, completely losing sight of the fact that matrimonial relationships require adjustments from both sides, and a willingness to stay together. The mere say of such willingness would not suffice.
2. It is no doubt true that the divorce legislations in India are based on the 'fault theory', i.e., no party should take advantage of his/her own fault, and that the ground of irretrievable breakdown of marriage, as yet, has not been inserted in the divorce law, despite a debate on this aspect by the Law Commission in two reports. We, however, find that there are various judicial pronouncements where this Court, in exercise of its powers under Article 142 of the Constitution of India, has granted divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage; not only in cases where parties ultimately, before this Court, have agreed to do so but even otherwise. There is, thus, recognition of the futility of a completely failed marriage being continued only on paper. No doubt there is no consent of the respondent. But there is also, in real terms, no willingness of the parties, including of the respondent to live together.
3. There are only bitter memories and angst against each other. This angst has got extended in the case of the respondent to somehow not permit the appellant to get a decree of divorce and "live his life", forgetting that both parties would be able to live their lives in a better manner, separately, as both parties suffer from an obsession with legal proceedings, as reflected from the submissions before us.
4. In numerous cases, where a marriage is found to be a dead letter, the Court has exercised its extraordinary power under Article 142 of the Constitution of India to bring an end to it. The provisions of Article 142 of the Constitution provide a unique power to the Supreme Court, to do "complete justice" between the parties, i.e., where at times law or statute may not provide a remedy, the Court can extend itself to put a quietus to a dispute in a manner which would befit the facts of the case.
5. It is with this objective that we find it appropriate to take recourse to this provision in the present case. We, thus, exercising our jurisdiction under

Article 142 of the Constitution of India, grant a decree of divorce and dissolve the marriage inter-se the parties forthwith.

3. जब दोनों पक्ष सहमत हों तब ऐसी दशा में निश्चित रूप से सक्षम न्यायालय में तलाक की डिक्री प्राप्त करने हेतु जा सकते हैं किंतु जब एक पक्ष सहमत नहीं हो तब ऐसी दशा में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के उद्देश्य से, जबकि असुधारयोग्य विवाह विघटन की परिस्थितियाँ पैदा हो थी एवं दोनों पक्ष 22 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे थे, तलाक की डिक्री दी गई यद्यपि पत्नी का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से एकमुश्त रुपये 25 लाख की राशि भी स्वीकृति की गई (If both the parties to the marriage agree for separation permanently and/or consent for divorce, in that case, certainly both the parties can move the competent court for a decree of divorce by mutual consent. Only in a case where one of the parties do not agree and give consent, only the the powers under Article 142 of the Constitution of India are required to be invoked to do the substantial Justice between the parties, However, a lump sum permanent alimony, quantified at Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to granted to be paid) [[R. Srinivas Kumar Versus R. Shametha dated 14.10.2019](#)]-Hon. Supreme Court held that-

1. If both the parties to the marriage agree for separation permanently and/or consent for divorce, in that case, certainly both the parties can move the competent court for a decree of divorce by mutual consent. Only in a case where one of the parties do not agree and give consent, only the the powers under Article 142 of the Constitution of India are required to be invoked to do the substantial Justice between the parties, considering the facts and circumstances of the case. However, at the same time, the interest of the wife is also required to be protected financially so that she may not have to suffer financially in future and she may not have to depend upon others.
2. This Court, in a series of judgments, has exercised its inherent powers under Article 142 of the Constitution of India for dissolution of a marriage where the Court finds that the marriage is totally unworkable, emotionally dead, beyond salvage and has broken down irretrievably, even if the facts of the case do not provide a ground in law on which the divorce could be granted. In the present case, admittedly, the appellant-husband and the respondent-wife have been living separately for more than 22 years and it will not be possible for the parties to live together. Therefore, we are of the opinion that while protecting the interest of the respondent wife to compensate her by way of lump sum permanent alimony, this is a fit case to exercise the powers under Article 142 of the Constitution of India and to dissolve the marriage between the parties.



3. In view of the above and for the reasons stated above, the application for divorce filed by the appellant husband for dissolution of marriage is hereby allowed.
4. The marriage between the appellant husband and the respondent wife is ordered to be dissolved in exercise of powers under Article 142 of the Constitution of India on the condition and as agreed by the learned Senior Advocate appearing on behalf of the appellant- husband that the appellant husband shall pay to the respondent-wife a lump sum permanent alimony, quantified at Rs.20,00,000/ (Rupees Twenty Lakhs) to be paid directly to the respondent wife by way of demand draft within a period of eight weeks from today. Till the permanent alimony as above is paid to the respondent-wife, the appellant-husband to continue to pay the maintenance as being paid to her.

4. अधिनियम के तहत असुधारयोग्य विवाह विघटन मात्र अपने आप में. तलाक प्राप्त करने का आधार नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मात्र को सेक्शन 13 के तहत मानसिक क्रूरता नहीं कहा जा सकता. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के तलाक की डिक्री को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा गया ( Mere irretrievable breakdown of marriage by itself is not a ground provided under the statute for seeking dissolution of marriage and some misunderstanding in the instant case cannot be considered as infliction mental cruelty under section 13 . The Supreme Court after quashing the decree of divorce granted by High Court, upheld the decision of Lower Court) [[Ravinder Kaur Versus Manjeet Singh \(Dead\) Through Lrs. dated 21.08.2019](#)]- Hon.Supreme Court held that-

1. As already noticed, the High Court, while taking note of the nature of allegations made has proceeded on the basis that there is irretrievable breakdown of the marriage. Needless to mention that irretrievable breakdown of marriage by itself is not a ground provided under the statute for seeking dissolution of marriage.
2. Hence, merely because certain issues have been raised with regard to the same, even if it be on a misunderstanding in the instant facts, it cannot be considered as inflicting mental cruelty in the nature it is required for considering the petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act for dissolving the marriage. Though the learned counsel representing the respondents referred to the incidents by which the appellant had hurled false allegations against the respondent, presently when the respondent has died and in a circumstance where one of the legal representatives, namely Shri Iqbal Singh was examined as RW6 in support of the case of the appellant herein and the legal representatives No.1 and 3, though were majors had not been examined in the proceedings, any contention raised on their behalf would not be of any assistance to take any other view. Therefore, if all these aspects are kept in perspective, we are of the



view that the High Court was not justified in reversing the well considered judgment passed by the trial court.

**13 - क. विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष -** विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, उस दशा को छोड़कर जहाँ और जिस हद तक अर्जी धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायोचित समझता है तो विवाह-विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक-पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा।

**13 - A. Alternate relief in divorce proceedings -** In any proceeding under this Act, on a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clauses (ii), (vi) and (vii) of sub-section (1) of section 13, the Court may, if it considers it just so to do having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.

**13 - ख, पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद -**

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए या दोनों पक्षकार मिलकर विवाह-विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में, चाहे ऐसा विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो चाहे उसके पश्चात् इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी के उपस्थापित किये जाने की तारीख से छः मास के पश्चात् और अठारह मास के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, यदि इस बीच अर्जी वापिस नहीं ले ली गई हो तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसी वह ठीक समझे, करने के पश्चात् अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किये गये प्रकाशन सही हैं यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा।

**13 - B. Divorce by mutual consent -**

(1) Subject to the provisions of this Act a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district Court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.

(2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the Court

shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree.

#### **14. विवाह के एक वर्ष के अन्दर तलाक के लिये कोई याचिका पेश न की जायगी -**

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक आज्ञप्ति द्वारा विवाह के भंग के लिए याचिका की तारीख जब तक कि उस विवाह की तारीख से अर्जी के उपस्थापन की तारीख तक एक वर्ष बीत न चुका हो, न्यायालय ऐसी याचिका को ग्रहण न करेगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अपने से किये गये आवेदन पर याचिका को विवाह की तारीख से एक वर्ष व्यपगत होने से पहले पेश करने के लिये समनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला याचिकादाता द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने का या प्रत्युत्तरदाता की असाधारण दुराचारिता का है, किन्तु यदि न्यायालय को याचिका की सुनवाई पर यह प्रतीत होता है कि याचिकादाता ने याचिका पेश करने के लिए इजाजत किसी मिथ्या व्यपदेशन या मामले के प्रकार के सम्बन्ध में किसी मिथ्या व्यपदेशन या किसी छिपावट से अभिप्राप्त की थी तो यदि न्यायालय आज्ञप्ति दे तो इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकेगा कि जब तक विवाह की तारीख से एक वर्ष का अवसान न हो जाय, तब तक वह आज्ञप्ति प्रभावशील न होगी या याचिका को ऐसी किसी याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा जो कि उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों पर उक्त एक वर्ष के अवसान के पश्चात् दी जाये जैसे कि ऐसे खारिज की गई याचिका के समर्थन में अभिकथित किये गये हों।

(2) विवाह की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व तलाक के लिए याचिका पेश करने की इजाजत के लिये इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से हुई किसी संतति के हितों और इस बात को भी कि क्या पक्षकारों के बीच उक्त एक वर्ष के अवसान से पूर्व मेल-मिलाप की कोई युक्तियुक्त सम्भाव्यता है या नहीं, ध्यान में रखेगा।

#### **14. No petition for divorce to be presented within one year of marriage -**

(1) notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any Court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce, unless at the date of the presentation of the petition one year has elapsed] since the date of the marriage:

Provided that the Court may, upon application made to it in accordance with such rules as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented [before one year has elapsed] since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but, if it appears to the Court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the Court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the [expiry of

one year] from the date of the marriage or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after the '[expiration of the said one year] upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so dismissed.

(2) In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of one year from the date of the marriage, the Court shall have regard to the interests of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said one year.

**15. कब तलाक-प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे -** जबकि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा।

**15. Divorced persons when may marry again —** When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or, if there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again.

**16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता -**

(1) इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का कोई अपत्य, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, धर्मज होगा, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से पूर्व हुआ हो या पश्चात् और चाहे उस विवाह के सम्बन्ध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मन्जूर की गई हो या नहीं और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं।

(2) जहाँ धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के सम्बन्ध में अकृतता की डिक्री मन्जूर की जाती है, वहाँ डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किये जाने के बजाय विघटित किया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जायेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे विवाह के किसी अपत्य को, जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता-पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में या सम्पत्ति के प्रति कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता-पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अजित करने में असमर्थ होता।

## 16. Legitimacy of children of void and voidable marriages -

(1) Notwithstanding that marriage is null and void under section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid, shall be legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this Act and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this Act.

(2) Where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12, any child begotten or conceived before the decree is made, who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the decree of nullity.

(3) Nothing contained in sub-section (1) or sub-section (2) shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a decree of nullity under section 12, any rights in or to the property of any person, other than the parents, in any case where, but for the passing of this Act, such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents.

**17. द्विविवाह के लिये दण्ड -** यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में ऐसे विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम 45) की धारा 494 और 495 के उपबन्ध तदनुकूल लागू होंगे।

**17. Punishment of bigamy -** Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this Act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living; and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall apply accordingly.

**18. हिन्दू विवाह के लिये कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दण्ड -** प्रत्येक व्यक्ति जो कि धारा 5 के खण्ड (iii), (iv) तथा (v) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठित करा लेता है।

(क) धारा 5 के खण्ड (iii) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में कठोर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से;

(ख) धारा 5 के खण्ड (iv) या खण्ड (v) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में सादे कारावास से जो एक महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ग) \*\*\*\*

## **18. Punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage. –**

Every person who procures a marriage of himself or herself or to be solemnized under this Act in contravention of the conditions specified in clauses (iii), (iv), and (v) of Section 5 shall be punishable–

(a) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iii) of Section 5, with simple imprisonment which may extend to fifteen days, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;

(b) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iv) or clause (v) of Section 5, with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;

(c) Clause (c) omitted by Act 2 of 1978.

### **क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया**

**19. वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जायेगी –** इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थापित की जायेगी जिसकी साधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर –

(i) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या

(ii) प्रत्यर्थी, अर्जी के उपस्थापन के समय, निवास करता है; या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, या

(iii-क) पत्नी के अर्जीदार होने की दशा में, याचिका प्रस्तुत करने वाले दिनांक को, जहाँ वह निवास कर रही है; या

(iv) अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, यह ऐसे मामले में, जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्यक्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है। अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के । भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में, यदि वह जीवित होता तो, स्वाभाविकतया सुना होता ।

### **Jurisdiction and Procedure**

## **19. Court to which petition shall be presented–**

Every petition under this Act shall be presented to the District Court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction:

(i) the marriage was solemnized, or

(ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides, or

(iii) the parties to the marriage last resided together, or

(iv) the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, in a case where the respondent is at that time, residing outside the territories to which this Act extends, or has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive.

**20. अर्जियों की अन्तर्वस्तु और सत्यापन --** (1) इस धारा के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे और धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई दुस्सन्धि नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अन्तर्विष्ट कथन वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किये जायेंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे।

## **20. Contents and verification of Petitions. –**

(1) Every petition presented under this Act shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claims to relief is founded and, except in a petition under Section 11, shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage.

(2) The statements contained in every petition under this Act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of plaints, and may, at the hearing, be referred to as evidence.

**21. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना --** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के और उन नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए, अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियाँ जहाँ तक हो सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित होगी।

**21. Application of Act 5 of 1908. –** Subject to the other provisions contained in this Act and to such rules as the High Court may make in this behalf all proceedings under this Act shall be regulated, as far as may be, by the Code of Civil Procedure, 1908.

## **21-क. कुछ मामलों में अर्जियों को अन्तरित करने की शक्ति --** (1) जहाँ

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है; और



(ख) उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिये या धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भिन्न राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है, वहाँ ऐसी अर्जियों के सम्बन्ध में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जिसे उपधारा (1) लागू होती है :

(क) यदि ऐसी अर्जियाँ एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोनों अर्जियों का विचारण और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी

(ख) यदि ऐसी अर्जियाँ भिन्न-भिन्न जिला न्यायालयों में पेश की जाती हैं तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अन्तरित की जाएगी जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी, और दोनों अर्जियों की सुनवाई और उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया

जाएगा जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी ।

(3) ऐसे मामले में, जिसे उपधारा (2) को खण्ड (ख) लागू होता है, यथास्थिति, वह न्यायालय या सरकार, जो किसी वाद या कार्यवाही को उस जिला न्यायालय से, जिसमें बाद वाली अर्जी पेश की गई है, उस न्यायालय को जिसमें पहले वाली अर्जी लम्बित है, अन्तरित करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सक्षम है, ऐसी बाद वाली अर्जी का अन्तरण करने के लिए अपनी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उक्त संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त की गई है ।

## **21 - A. Power to transfer petitions in certain cases -**

(1) Where -

(a) a petition under this Act has been presented to a District Court having jurisdiction by a party to marriage praying for a decree for a judicial separation under Section 10 or of a decree of divorce under Section 13; and

(b) another petition under this Act has been presented thereafter by the other party to the marriage praying for a decree for judicial separation under Section 10 or for a decree of divorce under Section 13 on any ground, whether in the same District Court or in a different District Court, in the same State or in a different State, the petitions shall be dealt with as specified in sub-section (2).

(2) In a case where sub-section (1) applies,-

(a) if the petitions are presented to the same District Court, both the petitions shall be tried and heard together by that District Court;

(b) if the petition are presented to different District Courts, the petition presented later shall be transferred to the District Court in which the earlier petition was presented and both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which the earlier petition was presented.

(3) In a case where clause (b) of sub-section (2) applies, the court or the Government, as the case may be, competent under the Code of Civil Procedure, 5 of 1908 to transfer any suit or proceeding from this District Court in which the later petition has been presented to the district court in which the earlier petition is pending, shall exercise its powers to transfer such later petition as if it had been empowered so to do under the said Code.

### **21-ख. इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध --**

(1) इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण, जहाँ तक कि न्याय के हित से संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन-प्रतिदिन तब तक निरन्तर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए किन्तु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिये स्थगन करना उन कारणों से आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किये जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहाँ तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा और प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से छह मास के अन्दर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहाँ तक सम्भव हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से तीन मास के अन्दर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

### **21-B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under the Act. -**

(1) The trial of a petition under this Act, shall, so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(2) Every petition under this Act shall be tried as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice of the petition on the respondent.

(3) Every appeal under this Act shall be heard as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to conclude the hearing within three months from the date of service of notice of appeal on the respondent.



**21-ग. दस्तावेजी साक्ष्य --** किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज साक्ष्य में इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगी कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

**21.-C. Documentary evidence. -** Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this Act on the ground that it is not duly stamped or registered.

## **22. कार्यवाहियों का बन्द कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना --**

(1) इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही बन्द कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के लिये ऐसी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा किन्तु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित किया गया है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

## **22. Proceedings to be in camera and may not be printed or published. -**

(1) Every proceedings under this Act shall be conducted in camera and it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with the previous permission of the Court.

(2) If any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions contained in sub-section (1), he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

## **23 - कार्यवाहियों में डिक्री -**

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, न्यायालय का समाधान हो जाए कि

(क) अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उसके द्वारा धारा 5 के खंड (ii) के उपखण्ड (क), उपखंड (ख) या उपखण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया है। अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या नियोग्यता का किसी प्रकार फायदा नहीं उठा रहा या उठा रही है, और

(ख) जहाँ कि अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट आधार हो वहाँ न तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसने उनका मौनानुमोदन या उपमर्षण किया है अथवा जहाँ कि अर्जी का आधार क्रूरता हो वहाँ अर्जीदार ने उस क्रूरता का किसी प्रकार उपमर्षण नहीं किया है, और

(खख) जब विवाह-विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर चाहा गया है, और ऐसे सम्मति बल, कपट या असम्यक असर द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गई है, और

(ग) अर्जी (जो धारा 11 के अधीन पेश की गई अर्जी नहीं है) प्रत्यर्थी के साथ दस्संधि करके उपस्थापित या अभियोजित नहीं की जाती है, और

(घ) कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है, और

(ङ) अनुतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई अन्य वैध आधार नहीं है, तो ऐसी ही दशा में, किन्तु अन्यथा नहीं, न्यायालय तदनुसार ऐसा अनुतोष डिक्री कर देगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व यह न्यायालय का प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी हर दशा में, जहाँ कि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना सम्भव हो, पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप कराने का पूर्ण प्रयास करे परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ii), खण्ड (iii), खण्ड (iv), खण्ड (v), खण्ड (vi) या खण्ड (vii) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर अनुतोष चाहा गया है।

(3) ऐसा मेल-मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय, यदि पक्षकार ऐसा चाहे तो या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे, तो कार्यवाहियों को 15 दिन से अनधिक की युक्तियुक्त कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को या यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल-मिलाप कराया जा सकता है या नहीं तथा करा दिया गया है या नहीं और न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा

(4) ऐसे हर मामले में, जिसमें विवाह का विघटन विवाह-विच्छेद द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रति मुफ्त देगा।

### **23. Decree in proceedings.-**

(1) In any proceeding under this Act, whether defended or not, if the Court is satisfied that-

(a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner except in cases where the relief is sought by him on the grounds specified in sub-clause (a), sub-clause (b) and sub-clause (c) of clause (ii) of Section 5 is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief, and

(b) where the ground of the petition is the ground specified in clause (i) of sub-section (1) of Section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, and

(bb) when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence, and

(c) the petition not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in collusion with the respondent, and

(d) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding, and

(e) there is no other legal ground why relief should not be granted, then, and in such a case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly.

(2) Before proceeding to grant any relief under this Act, it shall be the duty of the Court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavor to bring about a reconciliation between the parties:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause (ii), clause (iii), clause (iv), clause (v), clause (vi) or clause (vii), of sub-section (1) of Section 13.

(3) For the purpose of aiding the Court in bringing about such reconciliation, the court may, if the parties so desire or if the Court thinks it just and proper so to do adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the Court if the parties fail to name any person, with directions to report to the Court as to whether reconciliation can be and has been effected and the court shall in disposing of the proceeding have due regard to the report.

(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.

**23-क. विवाह-विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष --** विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म, कूरता या अभित्यजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा बल्कि वह उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा और यदि अर्जीदार का जारकर्म, कूरता या अभित्यजन साबित हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की माँग करते हुए अर्जी उपस्थापित की होती।

**23-A. Relief for respondent in divorce and other proceedings. -** In any proceedings for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion,

but also make a counter-claim for any relief under this Act on that ground; and if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the Court may give to the respondent any relief under this Act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground.

**24. वाद लंबित रहते भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय --** जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि, यथास्थिति, पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो :

परन्तु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिये के आवेदन को, यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो, पर नोटिस की तामील से साठ दिनों में निपटाएंगे।

#### **24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings.-**

Where in any proceeding under this Act it appears to the Court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay the petitioner the expenses of the proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent, it may seem to the Court to be reasonable.

#### **25. स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण --**

(1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय, डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण-पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि, जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य सम्पत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन-काल से अनधिक अवधि के लिए संदत्त करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो, प्रत्यर्थी की स्थावर सम्पत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखण्डित कर सकेगा।

(3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है, पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाहबाह्य मैथुन किया है तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश का ऐसी रीति में, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, परिवर्तित, उपांतरित या विखण्डित कर सकेगा।

## **25. Permanent alimony and maintenance. –**

(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purposes by either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondent's own income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the Court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immoveable property of the respondent.

(2) If the Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.

(3) If the Court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this Section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste or if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.

**26. अपत्नों की अभिरक्षा --** इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तवय अपत्नों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल, समय-समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे और डिक्री के पश्चात् इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते ऐसी डिक्री या अन्तरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे और न्यायालय पूर्वतन किए गए किसी आदेश या उपबंध को समय-समय पर प्रतिसंहत या निलंबित कर सकेगा, अथवा उसमें फेरफार कर सकेगा :

परंतु भरण-पोषण और अवयस्क बालकों की शिक्षा सम्बन्धित आवेदन, लम्बित कार्यवाही में डिक्री प्राप्त करने के, को, यथासंभव प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील से साठ दिनों में निपटाएंगे।

**26. Custody of children.** – In any proceeding under this Act, the Court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceedings for obtaining such decree were still pending, and the Court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made.

## **27. सम्पत्ति का व्ययन --**

इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के बारे में, जो विवाह के अवसर पर या उनके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्त पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे।

## **27. Disposal of property. –**

In any proceeding under this Act, the Court may make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of marriage, which may belong jointly to both the husband and the wife.

## **28. डिक्रियों और आदेशों की अपीलें –**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियाँ, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।

(2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तभी अपीलनीय होंगे जब वे अन्तरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।

(3) केवल खर्चों के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी।

(4) इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के अन्दर की जाएगी।

## **28. Appeals from decrees and orders. –**

(1) All decrees made by Court in any proceeding under this Act shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable as decrees of the Court made in the



exercise of its original civil jurisdiction and every such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its original civil jurisdiction.

(2) Orders made by the Court in any proceedings under this Act, under Section 25 or Section 26 shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable if they are not interim orders and every such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in exercise of its original civil jurisdiction.

(3) There shall be no appeal under this section on subject of costs only.

(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the decree or order.

## **28-क. डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन --**

इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है।

## **28 (A) Enforcement of decrees and orders. –**

All decrees and orders made by the Court in any proceeding under this Act, shall be enforced in the like manner as the decrees and orders of the Court made in the exercise of its original civil jurisdiction for the time being enforced.

## **व्यावृत्तियाँ और निरसन**

## **29. व्यावृत्तियाँ --**

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिन्दुओं के बीच अनुष्ठापित ऐसा विवाह, जो अन्यथा विधिमान्य हो, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा हुआ न समझा जाएगा कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे अथवा, विभिन्न धर्मों, जातियों या एक ही जाति की विभिन्न उपजातियों के थे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात रुढ़ि से मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी जो किसी हिन्दू विवाह का, वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार हो।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होने वाली किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगी जो किसी विवाह को बातिल और शून्य घोषित करने के लिए या किसी विवाह को बातिल अथवा विघटित करने के लिए या न्यायिक पृथक्करण के लिए हो और इस अधिनियम के प्रारंभ

पर लंबित हो और ऐसी कोई भी कार्यवाही चलती रहेगी और अवधारित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) में अन्तर्विष्ट किसी ऐसे उपबंध पर प्रभाव न डालेगी जो हिन्दुओं के बीच उस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व चाहे पश्चात् अनुष्ठापित विवाहों के सम्बन्ध में हो।

## **29. Savings. -**

(1) A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this Act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belonged to the same gotra or pravara or belonged to different religion, castes or sub-divisions of the same caste.

(2) Nothing contained in this Act shall be deemed to affect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of a Hindu Marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act.

(3) Nothing contained in this Act shall affect any proceeding under any law for the time being in force for declaring any marriage to be null and void or for annulling or dissolving any marriage or for judicial, separation pending at the commencement of this Act, and any such proceeding may be continued and determined as if this Act had not been passed.

(4) Nothing contained in this Act shall be deemed to effect the provisions contained in the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), with respect to marriages between Hindus solemnized under that Act, whether before or after the commencement of this Act.

**30. निरसन --** निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा (26-12-1960 से) निरसित

**30. Repeals. -** (Repealed by the Repealing and Amendment Act, 1960 (58 of 1960), Sec. 2 and the First Schedule.)



